IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 5, Issue 2, January 2025

राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव

अक्षय कुलहरि, शोधार्थी, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू
डॉ. शिवकुमार, सहायकआचार्य, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू
डॉ. श्वेता मेहता, शोध निदेशक, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान

सारांश–राजस्थान में कोविड–19 के एक लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी के मामलों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसी किसी भी घटना के बावजूद ग्रामीण इलाकों में 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन का सबसे अधिकअसर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के ग्रामीण इलाकों में लौटने से कोविड–19 के फैलने और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के बिगड़ने की दोहरी मार पड़ी है। मौजूदा अध्ययन में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष बताते हैं कि राजस्थान में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले 400 मिलियन मजदूरों के इस संकट के दौरान गरीबी में और अधिक फंसने का जोखिम है। कम टेस्टिंग के कारण कोविड–19 मामलों की कम रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप सामुदायिक प्रसार हुआ। रिवर्स माइग्रेशन से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बना, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग गरीबहो गये। कोविड–19 का राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह का प्रभाव पड़ा। सरकारी आर्थिक पैकेज में मुख्य रूप से दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं, जबकि प्रवासी मजदूरों और सीमांत किसानों को बचाने के लिए नकद प्रोत्साहन और मजदूरी सब्सिडी जैसे अल्पकालिक उपाय दिए जाने चाहिए। सबसे बढ़कर, सिस्टम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती है।

कीवर्डः– कोविड–19, प्रवासी मजदूर, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था

परिचय

राजस्थान में कोविड–19 के एक लाख से अधिक पॉजिटिव मामलों के साथ एक नए स्तर पर पहुंचने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी के मामलों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसी किसी भी घटना के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन का भी बड़ा असर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में प्रवासियों के ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने से कोविड–19 के प्रसार और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के बिगड़ने की दोहरी मार पड़ी है। लॉकडाउन के दबाव में बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन एक अभूतपूर्व त्रासदी है जिसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। कोविड–19 को पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया था। वर्तमान में, यह नया वायरस 195 से अधिक देशों में फैला है। अधिकांश देशों में राष्ट्रीय आपातकाल और लॉकडाउन किये गये। दुनिया भर में 4 मिलियन से अधिक लोग कोविड–19 वायरस से प्रभावित हुये और लगभग 300 हजार लोगों ने अपनी जान गंवायी।

राजस्थान में राज्य सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) योजना आदि के तहत अर्थव्यवस्था और सबसे गरीब लोगों का ध्यान रखने की कोशिश की, लेकिन इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती है। प्रवासी श्रमिक सदियों से विकास के इंजन हैं जो दुनिया भर में किसी भी क्षेत्र की आर्थिक सफलता के लिए दिन–रात काम करते हैं। दूसरी ओर, वे सबसे कमजोर हैं और उन्हें किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच नहीं रही। शहरी क्षेत्रों से

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 5, Issue 2, January 2025

ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन रिवर्स माइग्रेशन का ग्रामीण राजस्थान की जनसांख्यिकी, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अधिकांश प्रवासी श्रमिक अतीत में सीमांत किसान थे, जिन्होंने बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए कृषि छोड़ दी और शहरी क्षेत्रों में चले गए। कृषि संकट के बीच जबरन रिवर्स माइग्रेशन लोगों पर गरीबी में गिरने का बड़ा खतरा पैदा करता है।

वर्तमान अध्ययन ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था पर रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की स्थिति और राजस्थान की योजना की सफलता का भी आकलन किया गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति और कम परीक्षण के कारण कोविड–19 मामलों में पूर्वाग्रह की जांच की गई है। अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के दीर्घकालिक और अल्पकालिक आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा की गई है। कृषि क्षेत्र की स्थिति और कृषि संकट से संबंधित मुद्दों की भी रिपोर्ट की गई है। कम परीक्षण के कारण कोविड–19 मामलों की कम रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप नए वायरस का सामुदायिक प्रसार होगा। रिवर्स माइग्रेशन कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पैदा करेगा, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग गरीबी में गिर जाएंगे।

अध्ययन के उद्देश्य

1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचे के अवलोकन के बारे में अध्ययन करना।
2. राजस्थान की कृषि की स्थिति और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों के बारे में अध्ययन करना।

अर्थव्यवस्था का अवलोकन

वर्ष 2020–21 के लिए राजस्थान की विकास संभावना 0.8 से 4.0 प्रतिशत के बीच थी। पूर्वानुमान की यह अस्थायी और व्यापक सीमा अनिश्चितता की सीमा के कारण थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020–21 में राजस्थान की विकास दर 1.9 प्रतिशत, वैश्विक विकास में 3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया। राजस्थान के वास्तविक विकास परिणाम विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं जैसे कि अर्थव्यवस्था को कितनी तेजी से खोला जाता है, नोवेल वायरस को कितनी तेजी से नियंत्रित किया जाता है और सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना बनाती है।

सरकार ने हाल ही में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की, लेकिन योजना का वास्तविक प्रभाव योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में निहित है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकास अनुमानों पर अधिकांश आकलन अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं, जिन्हें भविष्य में संशोधित किया जा सकता है। देश के आर्थिक परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए, वर्ष 2017–18 के लिए अर्थव्यवस्था के 12 प्रमुख क्षेत्रों के लिए सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) या कुल उत्पादन का आकलन किया गया है। तालिका 1 कुल जीवीए में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान दर्शाती है। अर्थव्यवस्था में एकल क्षेत्र के रूप में विनिर्माण का योगदान सबसे अधिक है, लेकिन सेवाओं का संयुक्त योगदान कुल जीवीए का 50 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका 1.प्रमुख आर्थिक गतिविधियों द्वारा उत्पादन (2017–18)

क्षेत्र	उत्पादन (करोड़ रुपये में)	कुल का प्रतिशत
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	2371342	9.373
खनन और उत्खनन	665387.9	2.630
विनिर्माण	8904660	35.196
बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	801456	3.168
निर्माण	2642395	10.444

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 5, Issue 2, January 2025

व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां	2244829	8.873
परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	1807438	7.144
वित्तीय सेवाएं	1014881	4.011
अचल संपत्ति, आवास का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं	2700357	10.673
लोक प्रशासन और रक्षा	907580.2	3.587
अन्य सेवाएँ	1239848	4.901
कुल	25300174	100

स्रोत:– रिसर्च फाउंडेशन ऑफ राजस्थान

स्वास्थ्य अवसंरचना

राजस्थान में, निजी स्वास्थ्य सेवा महंगी है और अधिकांश लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, जो जरूरत के समय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं। गंभीर कोविड–19 रोगियों के लिए, हमें गहन देखभाल इकाइयों और वेंटिलेटर जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सभी कोविड–19 पॉजिटिव मामलों को सरकारी अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया इसलिए, यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान और उसके जिले नोवेल वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना के मामले में कहाँ खड़े रहे। तालिका 2 राजस्थान और भारत के कोविड–19 से प्रमुख रूप से प्रभावित राज्य के स्वास्थ्य सेवा संकेतकों की रिपोर्ट करती है। राजस्थान में, प्रति 1000 जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तर (0.7), चिकित्सक (0. 7256) और नर्स (1.3757) जैसे स्वास्थ्य सेवा संकेतक नोवेल वायरस से प्रमुख रूप से प्रभावित हैं। भारत में मरने वालों की संख्या 50 हजार तक पहुँची और 1 मिलियन से अधिक लोग वायरस से प्रभावित हुये। अधिकांश जिले बुरी तरह प्रभावित थे और राजस्थान का वर्तमान स्वास्थ्य अवसंरचना गंभीर स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती है।

तालिका 2.राजस्थान और कोविड–19 से प्रमुख रूप से प्रभावित राज्यों का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा

राज्य	अस्पतालों में बिस्तर प्रति 1000 (2021)	चिकित्सक प्रति 1000 (2021)	नर्सें प्रति 1000 (2021)
महाराष्ट्र	2.9	2.5817	8.832
राजस्थान	0.7	0.7256	1.3757
उत्तर प्रदेश	2.9	2.7769	8.6354
बिहार	3.5	3.9588	5.6446
हरियाणा	3.1	3.7975	5.5113
पंजाब	6.6	3.2117	10.6163
मध्य प्रदेश	2.3	1.8693	7.5122
हिमाचल प्रदेश	6.4	2.9729	11.0149
झारखंड	8.2	4.0827	13.4373
उत्तराखंड	1.7	1.4862	1.5453

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 5, Issue 2, January 2025

तमिलनाडु	4.7	3.42	10.5284
कर्नाटक	3.8	1.6989	2.1491

स्रोतः– सांख्यिकी विभाग भारत

राजस्थान की कृषि की स्थिति

राजस्थान गाँवों का देश है, जहाँ अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि और कृषि से संबंधित सेवाएँ लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं। पिछले कुछ दशकों में, कृषि संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर भारी पलायन हुआ है। संरचनात्मक आर्थिक विकास सिद्धांत संक्रमण चरण में प्रत्येक अर्थव्यवस्था को पारंपरिक से आधुनिक क्षेत्र में ले जाता है। राजस्थान क्रय शक्ति समता के मामले में दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि देश की अधिकांश आबादी घोर गरीबी में रहती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उदारीकरण के बाद आईटी क्षेत्र से उच्च विकास ने राजस्थान को तेजी से बढ़ने में मदद की, लेकिन यह ग्रामीण और शहरी विभाजन के लिए भी जिम्मेदार है। पिछले दो दशकों में आईटी क्षेत्र में उच्च वृद्धि के बावजूद, कृषि अधिकांश आबादी के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से, कुल जीवीए में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के योगदान में पर्याप्त गिरावट आई है। कई अध्ययनों से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि संकट की पुष्टि होती है। कृषि में जीएफसीएफ साल दर साल घट रहा है।

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ

कोविड–19 दुनिया भर में कई आर्थिक और गैर–आर्थिक मोर्चों पर संकट लेकर आया है। व्यापार प्रतिबंध और श्रम गतिशीलता के कारण मांग और आपूर्ति में झटके लगें। राजस्थान में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत 81 प्रतिशत लोगों पर इसका असर पड़ेगा (आईएलओ, 2018)। अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक न्यूनतम वेतन या किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा के बिना जीवित हैं (शर्मा, 2020)। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2008) के बाद भी, केवल 5–6 प्रतिशत ने सामाजिक सुरक्षा के लिए नामांकन कराया। 2017–18 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 71.1 प्रतिशत के पास नौकरी अनुबंध नहीं था, 54.2प्रतिशत सवेतन अवकाश के लिए पात्र नहीं हैं और 49.6प्रतिशत के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है (मोहन, 2019)। कृषि क्षेत्र में कृषि संकट के बीच शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में वापसी या रिवर्स माइग्रेशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करता है।

विशिष्ट मुद्दे

वापसी या रिवर्स माइग्रेशनः– अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (2011) के अनुसार, वापसी प्रवास प्रस्थान के बिंदु पर वापस जाने की क्रिया है, यह किसी अन्य स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद लोगों का अपने मूल निवास स्थान पर वापस लौटना है। यह स्वैच्छिक वापसी या मजबूर प्रवास हो सकता है। प्रवास के कारण के बावजूद, वापसी ग्रामीण क्षेत्रों की जनसांख्यिकी, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। रिवर्स माइग्रेशन अवधि में जनसंख्या के आकार और विशेषताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। वायरस से संदूषण के डर के बीच लोगों के लिए समाज से एकीकृत होना बहुत कठिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में वापसी प्रवास का ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि कुछ मामलों में यह नाटकीय रूप से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में योगदान देता है। वर्तमान स्थिति में, राजस्थान में आंतरिक प्रवासी मजदूर लगभग 450 मिलियन हैं। वर्तमान में, गरीबी और भूख से अपनी जान बचाने के लिए अपने गंतव्य को छोड़कर आए प्रवासी खाली हाथ लौटे।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 5, Issue 2, January 2025

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार, राजस्थान में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत लगभग 400 मिलियन श्रमिकों के संकट के दौरान गरीबी में और अधिक फंसने का खतरा है।

कृषि संकट और रिवर्स माइग्रेशनः– पिछले दो दशकों से कृषि क्षेत्र में संकट है। राजस्थान में, अधिकांश किसान छोटे भूमिधारक हैं जो उत्पादकता में गिरावट, पानी की कमी आदि की समस्या का सामना कर रहे हैं। वापस लौटने वाले अधिकांश लोग अतीत में सीमांत किसान थे। रिवर्स माइग्रेशन से कृषि पर दबाव बढ़ेगा जो पहले से ही बोझिल है।

उत्पादक में गिरावट और उपभोक्ता मूल्य में वृद्धिः– रिवर्स माइग्रेशन के परिणामस्वरूप फसलों के उत्पादक मूल्य में और गिरावट आएगी जिससे कृषि मजदूरी और आय कम हो जाएगी। दूसरी ओर, कम उत्पादकता और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होगी जिसका मुख्य रूप से गरीब लोग प्रभावित होंगे।

ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धिः– रिवर्स माइग्रेशन, उत्पादक मूल्य में गिरावट और कृषि क्षेत्र पर बढ़ते दबाव से ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री ने 12 मई 2020 को राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के मेगा पैकेज की घोषणा की, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत था। मौजूदा पैकेज में पिछले पैकेज (पीएमजीकेवाई, आरबीआई लिक्विडिटी उपाय, ब्याज कटौती) शामिल हैं, जो जीडीपी का लगभग 4 प्रतिशत था। पैकेज का मुख्य फोकस भूमि, श्रम, लिक्विडिटी और कानून हैं जो कुटीर उद्योगों, एमएसएमई, मजदूरों और मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करेंगे।लंबे समय में आय की असमानताओं, क्षेत्रीय असंतुलन और प्रवासी श्रमिकों की हिस्सेदारी को कम करने के लिए उद्योगों और रोजगार का स्थानीयकरण समय की मांग है। ऋण प्रदान करने के अलावा, नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानून और व्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि जैसे संस्थागत कारकों पर भी काम करने की आवश्यकता है। विनिर्माण उद्योग में, प्रवासन या प्रवासी मजदूर विकास के इंजन हैं। कोविड–19 या कोविड के बाद की दुनिया में हमेशा विनिर्माण वस्तुओं की मांग रहेगी।

इसलिए, सरकार को इस तंत्र पर काम करना होगा कि कैसे इन प्रवासी मजदूरों को उनके संबंधित कामों में वापस लाया जाए। दूसरी ओर, कोविड–19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए जांच बढ़ाई जानी चाहिए। अल्पावधि में, प्रवासी मजदूरों और सीमांत किसानों को गरीबी और भुखमरी से बचाने के लिए नकद प्रोत्साहन जैसे उपाय दिए जाने चाहिए। इसी तरह अनौपचारिक क्षेत्र को भी वेतन सब्सिडी दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती है।

संदर्भ

1. बून, एल. (2020), "कोविड–19 के दुष्परिणामों से निपटनाः कोविड–19 के समय में अर्थशास्त्र"
2. सिंह, एम. के. और वाई. नियोगा (2020), "कोविड–19 प्रकोप का संक्रामक प्रभावः राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आपदा का एक और नुस्खा", पब्लिक अफेयर्स।
3. सिंह, बी.पी. (2014), "पीडीएसः स्वतंत्रता के बाद से इसके कामकाज और प्रभावशीलता की समीक्षा"।
4. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (2011), "अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कानूनः प्रवासन पर शब्दावली", दूसरा संस्करण, आईओएम, जिनेवा।
5. डेंडर, ए. और आर. गाजी (2020), "कोविड–19 के दौर में प्रवास और रिवर्स प्रवास", इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली 55(19)।